एआई से कारोबार को मिलेगी नई ताकत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गूगल प्रतिनिधिमंडल के साथ एआई और डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की

नई दिल्ली , 07 जुलाई केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकें देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप, निर्यातकों और स्थानीय कारोबारों को नई मजबूती प्रदान कर सकती हैं.

उन्होंने कहा कि नवाचार आधारित और तकनीक-संचालित विकास को गति देने के लिए सरकार तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है. पीयूष गोयल ने गूगल के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट (ऐड एंड कॉमर्स) विध्या श्रीनिवासन और गूगल इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना ने किया. बैठक में देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एआई और डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि एआई आधारित समाधानों को अपनाकर छोटे कारोबारों, स्टार्टअप और निर्यातकों को डिजिटल बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है. साथ ही तकनीक आधारित नवाचार को बढ़ावा देकर उनकी उत्पादकता, बाजार तक पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बैठक में एआई को तेजी से अपनाने, डिजिटल स्किलिंग को मजबूत करने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि सरकार और टेक कंपनियों के बीच प्रभावी सहयोग से एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों और कारोबारों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा.

मंत्री ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एमएसएमई और स्थानीय उद्यमों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए. इससे छोटे व्यवसाय आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे और वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर हासिल कर पाएंगे. इससे पहले सोमवार को ही पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत द्वारा किए जा रहे नए मुक्त व्यापार समझौते देश में विनिर्माण और नवाचार को नई गति दे रहे हैं.

अडानी कॉपर को मिली वैश्विक मान्यता

अहमदाबाद, 07 जुलाई अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई कच्छ कॉपर लिमिटेड को 'अडानी कॉपर' के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज का प्रमाणन प्राप्त हुआ है.

अडानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को बताया कि लंदन मेटर एक्सचेंज औद्योगिक धातुओं के वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र है. उसके द्वारा दी गयी यह स्वीकृति केसीएल की विनिर्माण उत्कृष्टता और जिम्मेदार सोर्सिंग का वैश्विक मानकों पार प्रमाणन है. इसके साथ ही, 10 जुलाई से एलएमई पर तांबे के वायदा अनुबंधों पर जारी किये जाने वाले वारंट के लिए पात्र अडानी कॉपर कैथोड की डिलीवरी संभव होगी.अडानी एंटरप्राइजेज में प्राकृतिक संसाधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कच्छ कॉपर लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक विनय प्रकाश ने कहा, 'तांबा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की रीढ़ है. एलएमई ब्रांड का दर्जा प्राप्त करना अडानी को दुनिया के अग्रणी तांबा उत्पादकों की श्रेणी में स्थापित करता है. इससे वैश्विक बाजार में अडानी कॉपर की स्वीकार्यता और बढ़ेगी. यह न केवल अंतरराष्ट्रीय धातु उद्योग में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा, बल्कि परिष्कृत तांबे के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है.'

2030 तक 60 नए एयरपोर्ट का लक्ष्य

2030 तक 55-60 नए हवाई अड्डों और 50-60 करोड़ यात्रियों की क्षमता

ष्करीब 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत

नयी दिल्ली, 07 जुलाई भारत का विमानन क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है. वर्ष 2030 तक देश में 55 से 60 नए हवाई अड्डों के निर्माण और 50 से 60 करोड़ यात्रियों की क्षमता विकसित करने की योजना है.

हालांकि, इस महत्वाकांक्षी विस्तार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक निवेश जुटाने और नए एयरपोर्टों को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना होगी. यह जानकारी भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी. वहीं, 30 नए हवाई अड्डों के जरिए 12 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की क्षमता विकसित करने के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ेगा. बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को देखते हुए विमानन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को अनिवार्य बताया गया है. ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए स्थिर क्रेडिट रेटिंग आउटलुक बरकरार रखा है. एजेंसी का मानना है कि लगातार बढ़ रही यात्री संख्या, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में तेजी और प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटरों पर घटते कर्ज के कारण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

हालांकि रिपोर्ट में यह भी आगाह किया गया है कि भारी निवेश और लंबी निर्माण अवधि के चलते वित्त वर्ष 2021 से 2027 के बीच एयरपोर्ट ऑपरेटरों के शुद्ध मुनाफे पर दबाव रह सकता है. बड़े निवेश की लागत और परियोजनाओं के लंबे समय तक पूरा होने से शुरुआती वर्षों में लाभप्रदता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारतीय विमानन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है. वर्ष 2014 में देश में 74 परिचालन हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 163 हो गई है. वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जनवरी के दौरान भारतीय हवाई अड्डों से लगभग 35 .05 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें 28 .18 करोड़ घरेलू और 6 .87 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे.

उतार-चढ़ाव बाद बाजार लुढ़का, ट्रेंट टूटा

मुंबई, 07 जुलाई घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही और प्रमुख सूचकांक दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुए. टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट का शेयर 12 फीसदी से ज्यादा गिर गया.

बीएसई का सेंसेक्स 104.35 अंक (0.13 प्रतिशत) टूटकर 78,180.72 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 31.65 अंक यानी 0.13 फीसदी नीचे 24,398.70 अंक रहा. दोनों प्रमुख सूचकांक सोमवार को ढाई महीने के उच्चतम स्तर पर रहे थे.

बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गयी. वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक स्थिर रहा जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.55 प्रतिशत फिसल गया.

ट्रेंट ने सोमवार को एक अपडेट में बताया था कि चालू वित्त वर्ष की 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में उसका राजस्व 19 फीसदी बढ़कर 5,666 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. यह वृद्धि बाजार के अनुमान से कम है जिसके कारण उसके शेयरों में बिकवाली देखी गयी. आईटी सेक्टर में सबसे अधिक तेजी देखी गयी.

स्कूट का थीमैटिक सेल, किराया 10,500 रुपये से

नयी दिल्ली, 07 जुलाई सिंगापुर एयरलाइंस की कम लागत वाली इकाई स्कूट ने मंगलवार को जुलाई थीमैटिक सेल की घोषणा की जिसके तहत किराया 10,500 रुपये से शुरू है.

कंपनी बताया कि टिकटों की बुकिंग 07 जुलाई से 12 जुलाई के बीच करायी जा सकती है. इस दौरान ग्राहक भारत से सिंगापुर होते हुए फुकेट के लिए इकोनॉमी क्लास में एकतरफा टिकट मात्र 10,500 रुपये से शुरू होने वाले किराये पर बुक कर सकेंगे.

सेल के तहत भारत के हर शहर से रियायती बुकिंग पर यात्रा की अवधि अलग-अलग रखी गयी है. अमृतसर से 13 सितंबर से 23 अक्टूबर 2026 के बीच यात्रा अवधि पर यह ऑफर मिलेगा.

बीएचईएल ने ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया

नई दिल्ली, 07 जुलाई: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और थाइसनक्रुप न्यूसेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक रणनीतिक समझौता किया है, जिससे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र प्रणाली का चरणबद्ध स्वदेशीकरण और स्थानीय विनिर्माण संभव हो सकेगा.

यह सहयोग भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए बीएचईएल की परियोजना क्रियान्वयन क्षमताओं को और सुदृढ़ करेगा. बीएचईएल की ओर से श्री वाई श्रीनिवास राव, कार्यपालक निदेशक (हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट) और श्री सुतृप्तो डे, महाप्रबंधक एवं प्रमुख (न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिज़नेस) तथा थाइसनक्रुप न्यूसेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री किरण जोसेफ, सीईओ और श्री मनीष भोसले, निदेशकने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर महामहिम डॉ. फिलिप एकरमन, भारत एवं भूटान में जर्मनी के राजदूत, सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद) बीएचईएल, श्री एस एम रामनाथन, निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) बीएचईएल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बीएचईएल भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण कंपनियों में से एक है, जिसे पावर, ट्रांसमिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस, परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में दशकों का अनुभव प्राप्त है. कंपनी ने भारत के औद्योगिक अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अब अपनी इंजीनियरिंग, विनिर्माण एवं परियोजना निष्पादन क्षमताओं का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन सहित अन्य उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में कर रही है.

नौकरी छोड़ खड़ा किया सफल कारोबार

संजीव कुमार ने नौकरी छोड़ शुरू किया उद्योग, आज 2 .5 करोड़ रुपये सालाना कारोबार

पूर्णिया, 07 जुलाई . बिहार के पूर्णिया जिले के संजीव कुमार ने नौकरी करने के बजाय खुद का उद्यम स्थापित करने का सपना देखा और उसे साकार कर दिखाया.

बीएससी और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने निजी कंपनियों में सेल्स मैनेजर और फील्ड से जुड़े विभिन्न पदों पर काम किया. हालांकि, उनका लक्ष्य हमेशा अपना व्यवसाय शुरू करना था. इसी सोच के साथ उन्होंने नौकरी छोड़कर उद्यमिता की राह चुनी और आज उनकी कंपनी का सालाना कारोबार करीब 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

संजीव कुमार ने बैद्यनाथ एक्वा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर अपने कारोबारी सफर की शुरुआत की. उनका कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में बैंकिंग तथा निजी कंपनियों में काम किया, लेकिन नौकरी उन्हें वह संतुष्टि नहीं दे सकी जिसकी उन्हें तलाश थी. इसी अनुभव ने उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर के उद्योगों से की. धीरे-धीरे अनुभव और बाजार की समझ बढ़ने के साथ उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और वाटर प्लांट उद्योग में कदम रखा.

नई टैक्स व्यवस्था चुनने से पहले सोचें

नई दिल्ली, 07 जुलाई .. नई आयकर व्यवस्था को अपनाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

कम टैक्स दरों और अपेक्षाकृत सरल नियमों के कारण यह व्यवस्था कई लोगों को आकर्षित कर रही है. हालांकि कर विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कम टैक्स स्लैब देखकर नई व्यवस्था का चयन करना उचित नहीं है. आपकी सैलरी का ढांचा, निवेश, टैक्स छूट और वित्तीय दायित्व यह तय करते हैं कि आपके लिए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था अधिक लाभदायक होगी. सबसे पहले कर्मचारियों को यह देखना चाहिए कि उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ मिलता है या नहीं. यदि कोई कर्मचारी किराए के मकान में रहता है और एचआरए पर टैक्स छूट का दावा करता है, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था उसके लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि नई व्यवस्था में एचआरए पर छूट उपलब्ध नहीं है.

कोचीन शिपयार्ड में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली, 07 जुलाई .. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है. सरकार ने 'ऑफर फॉर सेल' के जरिए कंपनी में अपनी 5.04 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है.

इस बिक्री के लिए 1,400 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है. ओएफएस के तहत गैर-खुदरा (नॉन-रिटेल) निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होगी, जबकि खुदरा निवेशक 8 जुलाई को बोली लगा सकेंगे. सरकार सबसे पहले

कंपनी की 2.52 प्रतिशत पेड-अप इक्विटी बेस ऑफर के रूप में बिक्री के लिए पेश करेगी. इसके अलावा, यदि निवेशकों की मांग अपेक्षा से अधिक रहती है तो ग्रीन-शू विकल्प के तहत अतिरिक्त 2.52 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेची जा सकेगी. इस तरह कुल बिक्री 5.04 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

सरकार के लिए यह बिक्री वित्त वर्ष 2026-27 के विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इस ओएफएस में कंपनी की ओर से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार अपनी मौजूदा हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचेगी. यदि यह पूरी तरह सब्सक्राइब होता है तो कंपनी में पब्लिक फ्लोट बढ़ेगा और शेयरधारकों का आधार भी विस्तृत होगा.

समाचार विशेष

क्या तेजस्वी आरजेडी को फ्रंट से लीड नहीं करेंगे?

पटना. राजद में तेजस्वी यादव के लिए परिस्थितियां बदल रही हैं. अब लालू यादव के सामने ही वरिष्ठ नेता तेजस्वी की कमियों के बारे में सार्वजनिक चर्चा करने लगे हैं. उम्रदराज लालू यादव चाह कर भी इसे रोक नहीं पाये. उत्तराधिकार पाना अलग बात है और लीडर बनना अलग बात है.

जब तक कैप्टन फ्रंट से लीड नहीं करता, वह टीम के सहयोगी खिलाड़ियों का विश्वास खोने लगता है. तेजस्वी टीम के कार्यकारी कप्तान तो बन गये लेकिन टीम को प्रेरित करने के लिए खुद बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे. अब आरोप लगा है कि तेजस्वी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सर्वसुलभ नेता नहीं है. बाहर से आने वाले कार्यकर्ता तीन-तीन दिन तक पटना में रुके रहते हैं लेकिन वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाते.

लीडर कब बनेंगे तेजस्वी यादव?- पिछले 21 साल में राजद करीब 17-18 साल तक सत्ता से बाहर ही रहा है. बीच में उसे कुछ समय के लिए इसलिए शासन में रहने का मौका मिला क्यों कि नीतीश कुमार ने साथ दिया. जब से तेजस्वी, लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी बने हैं, तब से उनके नेतृत्व में राजद दो विधानसभा चुनाव हार चुका है. लोकसभा चुनाव में भी एक बार शून्य तो एक बार चार के आंकड़े पर रहे. जाहिर है तेजस्वी यादव, लालू यादव का विकल्प नहीं हैं. लालू यादव ने जो करिश्मा किया तेजस्वी यादव उसकी छाया मात्र भी नहीं हैं. तेजस्वी लालू यादव के सियासी वारिस हो सकते हैं लेकिन उनका विकल्प नहीं.

अगर तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिलते तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? किसी भी दल की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं. लालू यादव भी अपने प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं के स्नेह के कारण ही इतने बड़े नेता बने.

मोदी-नीतीश की हिट जोड़ी से मुकाबला कैसे?

अभी भाजपा अपने सर्वोच्च दौर से गुजर रही है. इसकी आंधी में बड़े-बड़े बरगद उखड़ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार इसका प्रमाण है. एक तो भाजपा मजबूत हो रही है ऊपर से बिहार में नीतीश कुमार का नाम भी है. नीतीश कुमार भले दिल्ली चले गये हैं लेकिन उनके नाम का असर बिल्कुल कम नहीं हुआ है. नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार जैसी मजबूत जोड़ी से निपटने के लिए तेजस्वी को नये सिरे से विचार करना होगा. नये दौर की राजनीति के अनुरूप खुद को ढालना होगा.

डीके को कुर्सी मिली, पर टीम नहीं...

कर्नाटक में 20 मंत्री पद खाली, गुटबाजी में घिरी कांग्रेस?

बेंगलुरु. कर्नाटक में डीके. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बने एक महीना हो चुका है. लेकिन, राज्य सरकार में अभी सिर्फ 13 मंत्री ही काम कर रहे हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं, फिर भी कैबिनेट में 20 पद अब भी खाली हैं.

सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर राजनीतिक खींचतान और मंत्री पद के लिए चल रही लॉबिंग के कारण कैबिनेट विस्तार में लगातार देरी हो रही है. इसकी वजह से कई अहम विभागों को अब तक स्थायी मंत्री नहीं मिले हैं. यह स्थिति ऐसे समय में बनी है, जब राज्य सूखे, कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और कई प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा है.

अपने पूर्ववर्ती सिद्धारमैया के साथ सत्ता साझेदारी को लेकर लंबे समय तक चले विवाद के बाद 3 जून को डीके. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उम्मीद थी कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और अनिश्चितता खत्म हो जाएगी. लेकिन, एक महीने बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है. इसकी वजह पार्टी के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिशें और मंत्री पद को लेकर जारी खींचतान बताई जा रही है.

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य सिद्धारमैया ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है. वहीं, मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने से परहेज किया है.

...तो सरकार की नींव हिल जाएगी

विपक्ष ने देरी को लेकर बार-बार सरकार को निशाना बनाया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई. विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार को टालने के लिए चल रही एसआईआर का बहाना बना रहे हैं. मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उनकी सरकार की नींव हिल जाएगी. यही वजह है कि वे एसआईआर का बहाना बना रहे हैं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कैबिनेट विस्तार की जल्दबाजी में नहीं है.

भाजपा में बढ़ रहा अजा नेताओं का कद

नई दिल्ली. दिल्ली की चुनावी राजनीति में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. भाजपा के लिए इन्हें अपने साथ जोड़ने की चुनौती रहती है.

अगले वर्ष नगर निगम चुनाव होना है. जिलों की टीम गठित करने में इसे ध्यान रखा जा रहा है. यही कारण है अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे कि इस वर्ग में पार्टी का आधार मजबूत हो सके. 14 संगठनात्मक जिलों में से अब तक घोषित 12 जिलों की टीम में इस वर्ग के 35 नेताओं को शामिल किया गया है. आने वाले समय में इनके बीच सक्रियता बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम भी शुरू हो सकते हैं.

दिल्ली नगर निगम में 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से मात्र छह में भाजपा के पार्षद हैं. विधानसभा में 12 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं. वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली थी.

विशेष | 1 घंटे बंद कमरे में क्या बात हुई! समझें सियासी मायने

जया ने ममता से क्यों की गुपचुप मुलाकात?

कोलकाता. यहां की सियासत में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने सबको चौंका दिया है. समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अचानक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर दस्तक दी. यह मुलाकात इतनी अचानक थी कि हर कोई हैरान रह गया.

गौर करने वाली बात यह रही कि जया बच्चन टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की कार में सवार होकर पहुंचीं. वहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने खुद उनका स्वागत किया. राज्य विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें इस मुलाकात के कई गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. लोगों का ध्यान इस बात पर है कि आखिर एक घंटे की इस लंबी बातचीत के पीछे असली एजेंडा क्या था.

एक घंटे की मीटिंग में क्या खिचड़ी पकी?- सूत्रों की मानें तो ममता बनर्जी और जया बच्चन के बीच यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली. दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट बताया. उन्होंने कहा कि ममता और जया के बीच पुराना और पारिवारिक रिश्ता है. हालांकि, सियासी जानकारों का सोचना कुछ और है. 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ममता बनर्जी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, जिस पर अदालत में सुनवाई भी चल रही है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहले कोलकाता आकर ममता बनर्जी से मिल चुके हैं.

सपा रिश्ते बचाए रखने के लिए गंभीर

जया का जाना यह साबित करता है कि सपा इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए गंभीर है. यह दौरा न केवल गठबंधन के लिए जरूरी था, बल्कि ममता को यह भरोसा दिलाने के लिए भी था कि मुश्किल समय में सपा उनके साथ खड़ी है. बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां हर मुलाकात एक नई चर्चा को जन्म दे रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मुलाकात बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगी या फिर यह महज कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगी.